भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1790
उत्तर देने की तारीख 13 दिसम्बर, 2023

बीएसएनएल और एमटीएनएल

1790. श्री श्याम सिंह यादव:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी दूरसंचार कंपनियाँ बीएसएनएल तथा एमटीएनएल लाभप्रद हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनके पुनरुथान के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को प्राइवेट दूरसंचार कंपनियों के समक्ष प्रतियोगिता में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) और (ग) सरकार ने वर्ष 2019 में लगभग 69,021 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान करके बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिससे बीएसएनएल/एमटीएनएल की प्रचालनात्मक लागत में कमी आई है। वर्ष 2022 का लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये पुनरुद्धार का पैकेज नया पूंजी निवेश करने, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण आदि पर केंद्रित था। इसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल और एमटीएनएल ने वर्ष 2020-21 से प्रचालनात्मक लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 07.06.2023 को इक्विटी निवेश के माध्यम से लगभग 89,047 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ बीएसएनएल को 4जी/5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया।

सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अनुसार, बीएसएनएल ने 4जी सेवाओं के रॉलआउट के लिए 1 लाख स्वदेशी रूप से विकसित साइटों के लिए क्रय आदेश दिए हैं। बीएसएनएल होम फाइबर सेगमेंट पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है और दिनांक 30.09.2023 तक 32,99,535 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

*****